



बजट में 3 साल का रोडमैप

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट

10428 करोड़ की बढ़ी राशि वीवीजीरामजी पर खर्च की तैयारी

8 वीं तक के बच्चों को अब ट्रेटा पैक में दूध पिलाएगी सरकार

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 18 फरवरी. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया. बजट में एक वर्ष के भीतर ही सरकार की प्राथमिकता का दायरा बढ़ गया है. सरकार अब ज्ञान के बजाय ज्ञानी पर फोकस करेगी. अब तक बजट का फोकस गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति पर था, लेकिन अब इनमें दो आई यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को भी जोड़ दिया गया है. इस तरह अब प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास और औद्योगिक निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने रोलिंग बजट तैयार किया है. बजट का आकार अगले तीन वर्ष तक कैसे रहेगा, ये अभी ये तय हो गया है. ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. सबसे बड़ी बात ये कि बजट में पिछले वर्ष की तरह ही किसी भी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया है. यानी सीधे तौर पर लोगों की जेब पर बजट का कोई असर नहीं होगा. बजट में वित्त विभाग का फायनेंस मैनेजमेंट साफ नजर आ रहा है. वित्तीय



बजट में 11 फीसदी बढ़ोतरी का दावा

बजट में इस बार 11 फीसदी बढ़ोतरी का दावा किया गया है. ये दावा संशोधित बजट के आधार पर किया गया है. संशोधित बजट 3 लाख 95 हजार करोड़ और नया बजट 4 लाख 38 हजार करोड़ के हिसाब से देखें तो इसमें 43296 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि संशोधित बजट के मुकाबले 11 फीसदी अधिक है. लेकिन यदि पिछले वर्ष के 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ के बजट के हिसाब से देखें तो इस बार बजट में महज 17285 करोड़ रुपए की ही बढ़ोतरी हुई है. यदि इस हिसाब से देखें तो ये 5 फीसदी से भी कम है. 2028 तक बजट 7.28 लाख करोड़ का होगा.

वर्ष 2026-27 के लिए पहले के अनुमानों और उम्मीदों से कम महज 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट ही पेश किया गया है. वर्ष 2025-26 की अवधि में 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. तब सरकार ने दावा किया था कि उसने बजट

में 15 फीसदी की बढ़ी बढ़ोतरी की है, लेकिन अब इस दावे का गुबार निकल गया है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट का आकार घटाकर 3 लाख 95 हजार 21 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है. इस तरह मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में 26 हजार 11 करोड़ रुपए की कमी हो गई है.

ये नई योजनाएं होंगी शुरू

लाइली बहनों की झोली में आएंगे 23883 करोड़ : बजट में मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना के लिए 23883 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का इंतजाम किया गया है. मद्र में ये योजना फ्री बिज की सबसे बड़ी योजना बन गई है, जिसमें एक करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के खाते में सीधे 1500 रुपए की राशि प्रतिमाह मिल रही है. इसमें अब लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी, अगले विधानसभा चुनाव तक ये राशि बढ़कर 3 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुंच सकती है. बजट में लाइली लक्ष्मी योजना के लिए 1801 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बजट में किए प्रावधानों के हिसाब से महिलाओं पर एक लाख 27 हजार करोड़ रुपए की कुल राशि खर्च होगी.

वीवीजी रामजी पर 10428 करोड़ खर्च करेगी सरकार : ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऑन डिमांड काम देने पर एक वर्ष में 10428 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी. विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण यानी वीवीजी रामजी योजना के लिए सरकार ने राशि का इंतजाम कर दिया है.

पहली बार पूंजीगत व्यय एक लाख करोड़ के अधिक : नए बजट में पहली बार पूंजीगत व्यय का आंकड़ा एक लाख करोड़ को पार कर गया है. इस बार अतिरिक्त बजट संसाधन के साथ ही पूंजीगत मद में एक लाख 6 हजार 156 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इससे प्रदेश में अधोसंरचना विकास के ज्यादा काम हो सकेंगे. यानी बांध, सड़क, नहर, पुल, पुलिया, भवन बनाने के साथ ही बिजली क्षेत्र में नए प्लांट लगाए जा सकेंगे. (शेष पृष्ठ 12 पर)

मोदी से मिले स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज

रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

नयी दिल्ली, 18 फरवरी. 'एआई इम्पैक्ट समिट' में शामिल होने आए स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत-स्पेन संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया. दोनों नेताओं ने विशेष रूप से रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.

मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि बैठक सार्थक रही और दोनों देशों ने 2026 को भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने के महत्व पर भी चर्चा की. मोदी ने कहा, विश्वविद्यालयों के बड़े प्रतिनिधिमंडल के भारत आने से शिक्षा एवं शोध सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता स्पेन के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा और दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्न करेगा. भारत और स्पेन के बीच 1956 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे. तब से दोनों देशों के संबंध लोकतंत्र और साझा मूल्यों पर आधारित रहे हैं. स्पेन वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारत का छटा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देश व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपसी साझेदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहे हैं.



स्पेन के राष्ट्रपति तुचिच से मोदी की बैठक

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में शामिल स्पेन के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर तुचिच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने रक्षा, विनिर्माण, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, उर्वरक और अवसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की. मुलाकात के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और स्पेन ने कई वर्षों से मिलकर कार्य किया है और आने वाले समय में संबंध और गति पाएंगे. भारत-स्पेन के संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण हैं और 1948 से राजनयिक संबंध जारी हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत पर आधारित हैं.

फिनलैंड के प्रधानमंत्री ओर्पो से मोदी की बैठक

एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्टेरी ओर्पो ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने 6जी, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, जैव ईंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग पर विचार-विमर्श किया. मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए ओर्पो के समर्थन से भारत-यूरोप संबंधों में नया स्वर्णिम युग शुरू होगा और व्यापार दोगुना करने के प्रयास को बल मिलेगा. भारत और फिनलैंड के संबंध 1949 से मैत्रीपूर्ण हैं और अब 5जी, 6जी, एआई, शिक्षा और हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार आधारित साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है.

LOVED IN
100
COUNTRIES

THE ALL NEW
pulsar 150 / 125
NOW WITH LEDS.

DARE THE DARK

एक्स शोरूम कीमत **₹84,293/-**

25 साल का उत्सव
₹7,000*
तक की सेविंग्स

₹3,000* तक की छूट | शून्य पीएफ | 5 फ्री सर्विसेस

N160 मॉडल पर उपलब्ध
PLATINA पर 3,000 की छूट

BAJAJ
THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN

pulsar
DEFINITELY DARING